

प्रेषक,

डा0एम0सी0जोशी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-4

देहरादून: दिनांक 19 जनवरी, 2015

विषय:-उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गोदी, जनपद अल्मोड़ा के प्रान्तीयकरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-नियोजन-3/943/उ0मा0वि0 गोदी (प्रान्तीय0) 2014-15 दिनांक 09 अप्रैल, 2014 के सन्दर्भ में श्री राज्यपाल महोदय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गोदी, जनपद अल्मोड़ा का प्रान्तीयकरण, शासनादेश निर्गत होने की तिथि अथवा वास्तविक रूप से अधिग्रहण की तिथि जो भी बाद में हो, से किये जाने एवं विद्यालय हेतु निम्नलिखित विवरणानुसार शासनादेश के दिनांक अथवा नियुक्ति की तिथि, जो भी बाद में हो, से 28 फरवरी, 2015 तक बशर्ते कि यह पद इसके पूर्व ही बिना किसी सूचना के समाप्त न कर दिये जायें, अस्थायी रूप से सृजित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र0सं0	पदनाम	वेतन बैंड (₹ में)	ग्रेड वेतन (₹ में)	सृजित पदों की संख्या
1.	प्रधानाध्यापक	15600-39100	5400	01
2.	सहायक अध्यापक, एल0टी0	9300-34600	4600	07
3.	कनिष्ठ सहायक	5200-20200	2000	02
4.	परिचारक	4440-7440	1800	01
योग:-				11 (ग्यारह पद)

2. उपर्युक्त पद शिक्षा के सम्बन्धित संवर्ग में अस्थायी वृद्धि के रूप में माने जायेंगे। इन पदों के पदधारकों को समय-समय पर जारी किये गये शासनादेशों के अनुसार वेतन, मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते देय होंगे।

3. श्री राज्यपाल महोदय प्रान्तीयकृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गोदी, जनपद अल्मोड़ा के प्रधानाध्यापक को अपने विद्यालय से सम्बन्धित व्ययों के लिए आहरण एवं वितरण अधिकारी भी घोषित करते हैं।

4. प्रान्तीयकरण की तिथि से इस विद्यालय का सम्पूर्ण व्यय सीधे सरकारी खर्च के रूप में वहन किया जायेगा तथा अन्य राजकीय विद्यालयों की भांति इस विद्यालय को भी जिला शिक्षा विभाग के प्रशासनिक अधिकार में दिया जायेगा एवं शिक्षा निदेशक, उत्तराखण्ड द्वारा प्रसारित सामान्य नियमों के अनुसार इसका संचालन किया जायेगा। प्रश्नगत विद्यालय की भूमि/भवन आदि सभी चल-अचल सम्पत्ति शासन को स्थानान्तरण कर दिया जायेगा। विद्यालय की अवशेष क्लेम की बकाया रकम, कोष चन्दे से प्राप्त रकम, दान से प्राप्त धनराशि तथा छात्रों से ली गई फीस की धनराशि आदि राजस्व प्राप्तियों के अन्तर्गत प्राप्त आय सम्बन्धित शीर्षक में जमा कर दी जायेगी। प्रान्तीयकरण पर यह विद्यालय बिना दायित्व तथा अन्य भार के शासन को सौंप दिया जायेगा। प्रान्तीयकरण से पहले की देनदारी यदि बाद में निकल आयी, तो उसका दायित्व शासन पर नहीं होगा।
5. उपर्युक्त विद्यालय में वास्तविक रूप से कार्य कर रहे वर्तमान स्टाफ को, जो प्रान्तीयकरण की तिथि को निर्धारित योग्यता रखते हों एवं अवसर की समानता के आधार पर व्यापक रूप से विज्ञापित पदों के सापेक्ष नियमानुसार पारदर्शी प्रक्रिया से नियुक्त हुए हों, को इस शासनादेश में स्वीकृत पदों के विपरीत अस्थायी रूप से नियुक्त किया जायेगा। इस प्रकार नियुक्त पदधारकों की ज्येष्ठता का निर्धारण का पूर्ण अधिकार शासन तथा शिक्षा विभाग को होगा। इन पदधारकों को राजकीय सेवा में नियमित रूप से नियोजित करना तभी सम्भव होगा, जब ये सक्षम अधिकारी अथवा लोक सेवा आयोग द्वारा अन्ततः योग्य घोषित कर दिये जायेंगे। ऐसे प्रश्नगत स्टाफ का वेतन सामान्य नियमों के अन्तर्गत निर्धारित होगा।
6. ऐसे पदधारक जो निर्धारित योग्यता न रखते हों अथवा जिन्हें शासन के सक्षम अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त न हो, की सरकारी सेवा में नियुक्ति सम्भव नहीं होगी। तदनुसार प्रश्नगत स्टाफ को स्पष्ट कर दिया जाय कि नियुक्ति अधिकारी द्वारा (अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा) लिखित रूप से दिये गये नोटिस के आधार पर उनकी सेवायें समाप्त कर दी जायेंगी। प्रान्तीयकरण के क्रम में अस्थाई अथवा नियमित रूप से नियुक्त ऐसे कार्मिक राज्य कर्मचारी के रूप में अपनी नई सेवा शर्तों को स्पष्ट रूप से लिखित में स्वीकार करेंगे।
7. भविष्य में परिचारक का पद वर्तमान पद धारक की सेवानिवृत्ति/स्थानान्तरण होने पर इनके स्थान पर नियमित नियुक्ति कदापि नहीं की जायेगी एवं आउट सोर्सिंग के माध्यम से ही कार्य सम्पादन कराया जायेगा।
8. इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि राजकीय सेवा में तदर्थ पी0टी0ए0 शिक्षकों का आमेलन किये जाने का कोई प्राविधान नहीं है। यदि विद्यालय में कोई पी0टी0ए0 शिक्षक कार्यरत हो तो तदनुसार प्रश्नगत स्टाफ को चेतावनी दे दी जाय कि नियुक्ति अधिकारी अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा लिखित रूप से दिये गये नोटिस के आधार पर उनकी सेवायें समाप्त कर दी जायेगी।
9. उक्त के सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2014-15 आय-व्ययक के अनुदान संख्या-11 के अधीन लेखाशीर्षक- 2202-सामान्य शिक्षा-02-माध्यमिक शिक्षा- आयोजनेतर-109-राजकीय माध्यमिक विद्यालय-08- अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों का प्रान्तीयकरण के अन्तर्गत सुसंगत मानक मदों के नामें वहन किया जायेगा।

10. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-73(NP)/XXVII(3)/2014-15 दिनांक 27 नवम्बर 2014 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डा०एम०सी०जोशी)
सचिव।

संख्या- 203 (1)/XXIV-4-4(07)/2014 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी को मा० मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ प्रेषित।
3. निजी सचिव, मा० शिक्षा मंत्री जी को मा० शिक्षा मंत्री जी के संज्ञानार्थ प्रेषित।
4. मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक, कुमायू मण्डल, नैनीताल।
5. जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, अल्मोड़ा।
6. मुख्य शिक्षा अधिकारी, अल्मोड़ा।
7. सचिव, शिक्षा एवं परीक्षा परिषद रामनगर, नैनीताल।
8. सम्बन्धित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
9. वित्त विभाग-3/नियोजन प्रकोष्ठ/शिक्षा अनुभाग-2 एवं शिक्षा अनुभाग-3।
10. एन०आई०सी०, सचिवालय परिसर, देहरादून।
11. गार्ड फाइल।

✓

आज्ञा से,
(श्रीप्रकाश तिवारी)
अनुसचिव।